aii ea

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

cz iea

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 1/2020

दिनांक : 01/01/2020

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

विषय : स्वागतम् वर्ष 2020

सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन, नववर्ष 2020 के आगमन पर तमाम बीमा कर्मचारियों के अलावा देश, प्रदेश एवं दुनियां के लाखों-लाख मेहनतकर्मी जमात को तहेदिल से क्रान्तिकारी अभिवादन, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है।

वक्त की अपनी रफ्तार है, उसे रोका नहीं जा सकता,उसी तरह दिन सप्ताह में, सप्ताह माह में और माह वर्ष में तब्दील हो जाता है और इसी कड़ी में वर्ष 2019 हमसे अलविदा हो गया है और 2020 का आगमन हुआ। हमारे लिए अनगिनत घटनाओं को समेटे विदा हुए वर्ष 2019 की अवधि का विश्लेषण, एक मेहनतकश वर्ग के नाते करना जरूरी और आवश्यक भी है। हमारे लिए 2019 का साल बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा है चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर।

दुनिया के स्तर पर हम देखते हैं कि विश्व में आर्थिक मंदी का दौर जारी है। इसके प्रभाव से विश्व में एक भय और डर का वातावरण बनता जा रहा है। दुनिया में अमेरिका, जर्मनी और चीन को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। अमरीकी-चीन व्यापार युद्ध ने इस संकट को और गहरा किया है। जैसा कि हम जानते हैं आर्थिक मंदी का असर अगर किसी पर सबसे ज्यादा होता है तो वह मेहनतकश वर्ग ही है। इसी के परिणामस्वरूप वर्ष 2019 ने अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक असमानता का वृहद नजारा भी देखा है, अधिकारियों और श्रमिकों के बीच वेतन का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। लैंगिक वेतन अंतर भी स्पष्ट नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वेतन वृद्धि 2016 के 2.4 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत हो चुकी है। रोजगार के अवसर दिनों-दिन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के द्वारा रोजगारमुक्त दुनिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण की भी जबर्दस्त चुनौती सामने आ रही है। मुनाफे की हवस ने पर्यावरण को दरकिनार कर दिया है। नोबेल अर्थशास्त्री जोसफ स्टिग्लिट्ज ने अपने हालिया लेख में इस हालत पर यह कहा है कि ''सच में मानव सभ्यता को खत्म ही कर देगा, नवउदारवाद, खुले बाजार को संपन्नता की कुंजी कहने वाले नवउदारवाद की साख खुद अंतिम सांसें गिन रहा है, उदारीकरण ने अपने 40 साल में लोकतंत्र को कमजोर किया है। वाल स्ट्रीट के पास देश के नागरिकों से अधिक राजनैतिक शक्ति आ गई है, नागरिकों से कहा जा रहा है कि वे अपनी मर्जी की नीतियां नहीं चुन सकते। विकास धीमा हो गया है, विकास के अधिकतर फायदे ऊपर के चंद लोगों तक सीमित हो गये हैं, शेयर बाजार उछालें मार रहा है लेकिन श्रमिकों का वेतन वहीं ठहरा हुआ है। इसका नाम उदारीकरण होने के बावजूद यह बिल्कुल भी उदार नहीं है।'' इसलिए समूची दुनियां में इस असमानता के विरुद्ध प्रतिरोध गूंज रहे हैं। एक ओर जहां साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के आक्रमण तीव्र हुए हैं तो दूसरी ओर मजदूर वर्ग का संघर्ष भी तीखा हुआ है। आने वाला समय में वैश्विक स्तर पर इसकेऔर भी तीखे होने की संभावना है।

जहां तक राष्ट्रीय परिस्थिति का सवाल है वर्ष 2019 भारत के लिहाज से किसी भी सूरत में 'सब ठीक है' नहीं कहा जा सकता। हर वर्ग चाहे मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, गृहणियां हों या छोटे मध्यम व्यापारी हर कोई परेशान है, त्रस्त है। 2014 में जिन वादों और दावों के साथ भाजपा ने सत्ता हासिल की उसे पूरा करना तो दूर वह केवल और केवल चंद पूंजीपतियों का साथ व उनका विकास के नारों में तब्दील हो गया है। यह सरकार चंद पूंजीपति घरानों के लिए ही कार्य कर रही है, यह बात स्पष्ट रूप से ऑक्सफॉम की रिपोर्ट से भी साफ हो गई है जिसके अनुसार 9 सबसे अमीर भारतीयों की संपदा आबादी के निचले 50 प्रतिशत लोगों की संपदा के बराबर है। लेकिन ऐन आम चुनाव के पहले पुलवामा हमला और फिर प्रतिक्रिया में

बालाकोट का आक्रमण के बाद एक ऐसा राष्ट्रवाद का मुद्दा सरकार के साथ-साथ चाटूकार मीडिया के माध्यम से बनाया गया, कि ये सभी मुद्दे चाहे रोजगार का हो, चाहे किसान का हो या फिर आर्थिक मंदी, गरीबी, भुखमरी, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, एक तरफ हाशिये पर चले गए, केवल और केवल 'राष्ट्रवाद' हावी रहा और इसी का परिणाम था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने एक बार फिर पहले से भी ज्यादा सीटों से सत्ता में पुनर्वापसी कर ली।

नई सरकार के आने के बाद से अर्थव्यवस्था के चरम संकट, गिरते जीडीपी, रोजगार के अवसर की समाप्ति, शिक्षा के व्यापारीकरण, किसानों की बढ़ती आत्महत्या, कारखानाबंदी, छंटनी, घटते उपभोग, बढ़ती मंहगाई, प्याज, दाल की आसमान छूती कीमतों जैसे सवालों पर जनता को राहत के कदम उठाने की बजाय सार्वजनिक क्षेत्रों की बोलियां लगाई जा रही हैं। श्रम कानूनों में संसदीय बहुमत का दुरुपयोग कर मनमाने परिवर्तन किये जा रहे हैं। रेल, रक्षा, बैंक, बीएसएनएल, खुदरा व्यापार, इस्पात, कोयला सबके निजीकरण तथा उसमें विदेशी पूंजी के प्रवेश (एफडीआई) का रास्ता साफ किया जा रहा है और जब देश के मजदूर और आम नागरिक के विरोध के स्वर एकजुट हो रहे हैं तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिये उनकी एकता को कमजोर करने व जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशें हुई हैं। नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता पंजी , कभी एनआरसी के माध्यम से व देश में भय का वातावरण बनाने और लोगों को अपनी नागरिकता प्रमाणित करने लाइनों में खड़ा करने का कुचक्र चलाया जा रहा है। नोटबंदी और जीएसटी की त्रासदी के बाद यह एक और त्रासदी थोपने और विभाजनकारी मुहिम को आगे बढ़ाने का ही उपक्रम है। धर्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान हमारी संविधान की मूल भावना पर ही हमला है। उसका परिणाम इस देश के संविधान और एकता को ही नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। इसके विरुद्ध आंदोलन जबर्दस्त रूप से सारे देश में फैल रहा है और उसे दबाने की हर संभव कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है।

बीमा उद्योग पर नजर डालें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग, वो चाहे जीवन बीमा निगम हो या फिर आम बीमा विपरीत आर्थिक परिवेश में भी निरंतर प्रगति के सोपान तय कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत स्वरूप पर हमले भी तेज हो रहे हैं। मोदी-2 सरकार के पहले बजट में ही बीमा क्षेत्र में इंटरमीडियरी के लिए 74 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी, एलआईसी को भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर विनिवेश याने निजीकरण का ऐलान और हाल ही में निजी उद्योगों की मांग के अनुरूप बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और सबसे खतरनाक इसके लिए किसी कानूनी संशोधन या संसद के अनुमोदन की बजाय आटोमेटिक रूट याने प्रशासनिक अधिसूचना से ही कर दिये जाने जैसे सुझावों के सामने आने से इस पर सरकार का चरित्र का और खुलासा ही हो रहा है। राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में 1 अगस्त 2017 से वेतन पुनर्निर्धारण लंबित है विगत वर्ष हमारे संघर्ष के चलते प्रबंधन ने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किया और 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। एआईआईईए ने स्पष्ट किया था कि यह हमारी अपेक्षाओं और उद्योग की देयक क्षमता के अनुरूप अपर्याप्त है और प्रबंधन को उस अनुरूप नये प्रस्ताव के साथ वार्ता आहूत करनी चाहिए। निश्चय ही इस वर्ष हमें इसे प्राप्त करने जुटना होगा। इस वर्ष हमारी अनेक लंबित समस्याओं का समाधान करने में भी हमें सफलता मिली । मोबाईल रीचार्ज, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति हेतु योजना प्रारंभ हुई। वर्ष 1986 के पूर्व जीवित सेवानिवृत्ति साथी/आश्रित के सहायतार्थ मेडिकल भत्ता रु. 24000 तथा आश्रित हेतु रु. 12000 प्रतिवर्ष प्रारंभ किया गया। एलटीसी योजना में 3000 किलोमीटर से बढ़कर 4500 किमी किया गया। एलटीसी योजना में हवाई यात्रा बुकिंग समस्या का निराकरण किया गया। बहुप्रतीक्षित पेंशन विकल्प योजना ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध हुआ। 8000 नये साथियों की नई भर्ती प्रारंभ हुई। अब चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नई भर्ती की मांग पर संघर्ष में जुटना होगा, साथ ही नई भर्ती तृतीय श्रेणी में जारी रखने भी हमें प्रयत्नशील रहना होगा।

इसी रोशनी में 8 जनवरी 2020 को पूरे देश के पैमाने पर विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से एक दिवसीय हड़ताल का आव्हान किया गया है और इसकी तैयारी भी जबर्दस्त चल रही है। इस हड़ताल के माध्यम से मोदी सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि मजदूर विरोधी कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2020 की शुरुआत ही संघर्ष के आगाज से हो रहा है और संघर्ष के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, स्पष्ट है। हम समस्त मेहनतकश अवाम को आह्वान करते हैं कि सरकार की जनविरोधी मजदूर विरोधी नीतियों को परास्त करने अपनी सांगठनिक मजबूती और एकता को सुदृढ़ कर इन तमाम गतिरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ें क्योकि वर्ष 2020 का यही पैगाम है कि न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, न हम झुकेंगे बल्कि अपना हक हर हाल में लेकर रहेंगे। एक बार पुन: नववर्ष के लिए हार्दिक अभिनंदन ।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)
महासचिव